दैनिक

पुष्पांजली टुडे

नई सोच, नई पहल

ग्वालियर, शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2019

■ ग्वालियर ■ वर्ष:02 ■ अंक: 339

■ पृष्ठ 8 ■ मूल्य : 2 रु.

न्यूज ट्रैक

नागरिकता बिल पर प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा रद्द

नई दिल्ली। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है। पीटीआई के अनुसार, उनकी यह यात्रा नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने से उत्पन्न स्थिति के चलते रद्द हुई है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई पहले जानकारी के अनुसार, मोमेन को गुरुवार शाम 5:20 पर भारत आना था। उनकी यह यात्रा तीन दिनों के लिए थी। मालूम हो कि नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। इससे पहले विधेयक को लोकसभा की भी मुहर मिल चुकी थी। इसको लेकर असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिल पारित होने के बाद से ही असम में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तथा इंटरनेट सेवाएं बंद होने से सैकड़ों यात्री गुवाहाटी हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। शहर से 30 किलोमीटर दूर बोरझार स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर और बाहर छात्रों से लेकर कामकाजी पेशेवर, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक की भीड़ देखी जा सकती है।

रानू मंडल से हिमेश रेशमिया ने काटी कन्नी, सवाल पूछे जाने पर गुस्से में आए

नई दिल्ली। रातों-रात सोशल मीडिया सेंसेशन बनी रानू मंडल इंटरनेट पर अभी तक छाई हुई हैं। रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना गुनगुनाते हुए रानू मंडल का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। लोगों ने इनकी आवाज को इस कदर पसंद किया था कि हिमेश रेशमिया ने जब इनका ये वीडियो देखा था तो तुरंत इन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए साइन कर लिया था। इसके बाद रानू मंडल कभी अपने मकेअप की वजह से तो कभी अपने गुस्से और एटीट्यूड की वजह से सुर्खियों में आईं। अब हिमेश रेशमिया रानू मंडल से परेशान होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई के एक कार्यक्रम में हिमेश रेशमिया को स्पॉट किया गया जहां मीडिया ने उनसे रानू मंडल से जुड़ा सवाल किया जिसके बाद वे गुस्से में आ गए और ये कहते दिखाई दिए कि मैं उनका कोई मैनेजर नहीं हूं। ये वही हिमेश रेशमिया हैं जिन्होंने रानू मंडल को अपनी फिल्म हैपी हार्डी में कई सारे गाने गुनगुनाने का मौका दिया था जिसमें से सबसे ज्यादा हिट 'तेरी मेरी कहानी' सॉन्ग हुआ था। हालांकि, देखा जाए तो हिमेश रेशमिया की फिल्म के बाद रानू मंडल को कई रिएलिटी शो का हिस्सा बनते देखा गया। लेकिन सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद उनका करियर अब हिचकोले खाता नजर आ रहा है।

सास-ससुर को घर में बंद कर दूसरे शहर गई बहू, ससुर की मौत

सीतापुर। सीतापुर शहर में एक धनाढ्य घर की बहू दो दिन पूर्व अपने बुजुर्ग सास-ससुर को घर में बंद कर गोरखपुर चली गई। इस बीच ससुर की मौत हो गई। दो दिन तक बुजुर्ग बालकनी पर नहीं दिखे तो बुधवार को पासपड़ोस के किसी व्यक्ति ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर ने घर के ऊपरी भाग में दरवाजे पर लगा ताला तुड़वाकर वृद्ध का शव बाहर निकालवाया। महिला कल्याण विभाग की टीम ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो उसने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए।

निर्भया केसः दोषी अक्षय की रिव्यू पिटिशन पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले के चार मुजरिमों में से एक अक्षय कुमार सिंह द्वारा मौत की सजा के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। अक्षय ने यह रिव्यू पिटिशन मंगलवार को दाखिल की थी। अक्षय कुमार सिंह ने तर्क दिया था कि मौत की सजा पर अमल अपराध को नहीं बल्कि सिर्फ अपराधी को मारता है। दिसंबर, 2012 में हुये सनसनीखेज निर्भया कांड में उच्चतम न्यायालय ने 2017 में चारों मुजरिमों की मौत की सजा के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया था। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने चारों को मौत की सजा के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि कर दी थी।

असम के 10 जिलों में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद

गुवाहाटी में पुलिस गोलीबारी में दो प्रदर्शनकारियों की मौत

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद असम समेत पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। असम के दस जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी गई है। गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एक व्यक्ति को मृत लाया गया था जबकि एक अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। पढ़ें, नागरिकता बिल को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी खास बातें-

असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) कुमार संजय कृष्णा ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट सेवा को जिन असम के 10 जिलों में 48 घंटों के लिए बंद किया गया है, उनके नाम लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप और कामरूप है। नागरिकता बिल-बांग्लादेश के विदेश मंत्री के बाद अब गृहमंत्री का भी भारत दौरा रद्द। नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सोनितपुर के बेहली में असम के हथकरघा मंत्री रंजीत दत्ता के आवास पर बृहस्पतिवार को हमला कर दिया। उधर तेजपुर तथा ढेकियाजुली शहरों में भी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है।असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने शहर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के बावजूद नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से संयम बरतने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की बृहस्पतिवार को अपील की।

असम के डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) के बस टर्मिनल को आग लगा दी। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग शहर के चौकीडिंगी इलाके में स्थित एएसटीसी टर्मिनल में पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ की तथा परिसर को आग लगा दी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के लोगों से एक वीडियो अपील में बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि असम समझौते की धारा छह की भावना के अनुरूप उनकी राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की रक्षा की जायेगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के अध्यक्ष के एम कादिर मोहीदीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ सिलसिलेवार प्रदर्शन करने की योजना बना रही है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इस असंवैधानिक विधेयक को मंजूरी नहीं देने की अपील की जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार में विभागों का बंटवारा

शिवसेना से एकनाथ शिंदे को मिला गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार में गुरुवार को विभागों का बंटवारा हो गया। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस को राजस्व, ऊर्जा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, वस्त्र, महिला एवं बाल कल्याण विभाग मिले। शिवसेना को सरकार में गृह, शहरी विकास मंत्रालय मिले हैं। वहीं, एनसीपी को महाराष्ट्र सरकार में वित्त, आवास, लोक स्वास्थ्य, सहकारी मंत्रालय मिले हैं। कांग्रेस से बालासाहेब थोराट को राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा आदि विभाग मिले हैं। एनसीपी के जयंत पाटिल को वित्त और योजना, आवास, खाद्य आपूर्ति और श्रम विभाग दिया गया है।

इसके अलावा शिवसेना से मंत्री एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया गया है। शिंदे को शहरी विकास, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और संसदीय कार्य विभाग भी मिला है। वहीं, एनसीपी नेता छगन भुजबल को ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, जल संसाधन आदि विभाग मिले हैं।

नागरिकता बिल पर पाकिस्तान ने किया कमेंट, तो भारत ने दी ये नसीहत

नई दिल्ली। लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर की गई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की टिप्पणी पर भारत ने सख्त नसीहत दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान को अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ सलूक पर ध्यान देना चाहिए।

विधेयक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की टिप्पणी का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले में टिप्पणी करने के बजाय अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ सलूक पर ध्यान देना चाहिए। इमरान

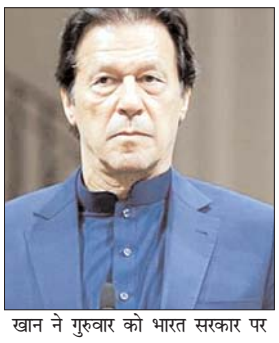

खान ने गुरुवार को भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि वह सुनियोजित तरीके से हिंदू सर्वोच्चवादी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है और इससे पहले कि देर हो जाए, विश्व को अवश्य ही कदम उठाना चाहिए।

महंगाई से परेशान लोग

तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति दर

नई दिल्ली, एजेंसी। खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर माह में बढ़कर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई। पिछले महीने अक्टूबर में यह 4.62 प्रतिशत पर थी। खाने पीने की वस्तुओं के दाम चढ़ने से नवंबर माह में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह इसका तीन साल का उच्चस्तर है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इसी साल अक्टूबर में 4.62 प्रतिशत और नवंबर, 2018 में 2.33 प्रतिशत रही थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार माह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 10.01 प्रतिशत पर पहुंच गई। अक्टूबर में

यह 7.89 प्रतिशत तथा एक साल पहले इसी महीने में 2.61 प्रतिशत थी। इससे पहले जुलाई, 2016 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.07 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन घटा-बिजली, खनन और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर महीने में 3.8 प्रतिशत घट गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के रूप में मापा जाने वाले औद्योगिक उत्पादन एक साल पहले इसी माह में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विनिर्माण क्षेत्र में नरमी दर्ज की गयी। इसमें अक्टूबर महीने में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि एक साल पहले इसी महीने में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आंकड़े के अनुसार बिजली उत्पादन में अक्टूबर 2019 में तीव्र 12.2 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि पिछले साल इसी महीने इसमें 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खनन उत्पादन भी आलोच्य महीने में 8 प्रतिशत गिरा जबकि पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में इसमें 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

नागरिकता बिल पर विरोध तेज

असम में प्रदर्शनकारियों ने विधायक के घर को जलाया

नई दिल्ली। नागरिकता बिल को लेकर असम में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने असम के चबुआ में विधायक बिनोद हजारिका के आवास को जला दिया। वहीं, सर्किल कार्यालय में आग भी लगा दी। नागरिकता बिल को लेकर जारी हिंसा के बीच असम में दस जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक की अवधि को गुरुवार की दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के वास्ते इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) संजय कृष्णा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में सात बजे इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं। गुवाहाटी में बड़ी संख्या में लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर उतरे और पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री के बाद अब गृहमंत्री का भी भारत दौरा रद्द

नई दिल्ली। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन द्वारा भारत दौरे को रद्द किए जाने के बाद बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने भी अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। दोनों का यह दौरा नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने से उत्पन्न स्थितियों के चलते हुआ है। न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, मोमेन ने गुरुवार से शुरू होने वाली अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा आज यहां पहुंचने के निर्धारित समय से चंद घंटे पहले अचानक रद्द कर दी।इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न संबंधी भारत के केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणियां असत्य हैं। वहीं, बांग्लादेश के गृह मंत्री खान को तीन दिवसीय भारत यात्रा पर मुख्यत-बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल होने शुक्रवार को शिलांग पहुंचना था।

मराठवाड़ा के मुद्दों पर अनशन करेंगी पंकजा मुंडे, पार्टी छोड़ने पर क्या दिया बयान

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की नेता पंकजा मुंडे ने गुरुवार को कहा है कि वे पार्टी नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं 27 जनवरी को मराठवाड़ा क्षेत्र के लंबित मुद्दों को लेकर अनशन करूंगी। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं समूचे महाराष्ट्र का दौरा करके गोपीनाथ मुंड के नाम पर बने संगठन के लिए काम करूंगी। इससे पहले बीते हफ्ते पंकजा मुंडे ने कहा था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रही हूं। दलबदल मेरे खून में नहीं है। भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा ने उन अफवाहों का भी खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि उनके ट्विटर परिचय से भाजपा को हटाने का मकसद अपनी पार्टी पर दबाव बनाना था।

गुरुवार को बुलाई थी बैठक-पंकजा मुंडे ने अपने पिता गोपीनाथ मुंडे की बरसी पर आज (12 दिसंबर) समर्थकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बारे में उन्होंने बीते दिनों कहा था कि वे आनेवाले आठ या दस दिन में बड़ा फैसला लेंगी।

झारखंड में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान

माफ होगा किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज अगर...

साहिबगंज (झारखंड)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार को चंद पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार बताते हुए वादा किया कि यदि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आती है तो सबसे पहले किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ करेगी। गांधी ने आज यहां अपने गठबंधन सहयोगी झामुमो के प्रत्याशी केतुबुद्दीन शेख के समर्थन में आयोजित जनसभा में यह बात कही। इन चुनावों में पहली बार उनके साथ मंच पर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। राहुल गांधी ने भाजपा नीत केन्द्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार देश के सिर्फ चुनिंदा 15-20 पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस-नीत गठबंधन की सरकार बनने पर आदिवासियों के जल, जंगल जमीन की रक्षा करने की बात भी कही। झारखंड विधानसभा चुनावों में चौथे और पांचवें चरण के लिए आयोजित चुनावी रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार

का लक्ष्य गरीबों का पैसा लेकर अंबानी और अडाणी की जेब में डालना है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज केन्द्र में जो सरकार काम कर रही है वह वास्तव पूंजीपतियों के हित में काम करने वाली सरकार है। वह झारखंड के आदिवासियों से जमीन छीनकर इन उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को लौटा दी। उन्होंने कहा कि ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि टाटा जैसी बड़ी कंपनी ने पांच वर्ष से अधिक समय से आदिवासियों की जमीन लेकर वहां उद्योग नहीं लगाया था। हमने कानून बनाया था कि जो भी उद्योगपति पांच वर्ष तक भी भूमि का उपयोग नहीं करेगा उससे जमीन वापस ले ली जायेगी और किसानों और आदिवासियों को लौटा दी जायेगी। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर दी और फिर जीएसटी लागू कर दी जिससे तमाम उद्योग बंद हो गये। छोटे व्यापारी और गरीब बर्बाद हो गये। लोगों के रोजगार छीन गए। गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपया देने से मना कर दिया लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा कर दिखाया। जबकि झारखंड में अभी भी किसानों को 1,300 रुपये प्रति क्विंटल ही धान का मूल्य मिल रहा है।

सम्पादकीय

चांसलर के अधिकार

ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन अगर राज्य और केंद्र में सरकार अलग-अलग दल की हो, तो राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनाव अक्सर उभर ही आते हैं। ऐसे तनावों का एक इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहा है, इसलिए वहां की सरकारों का राज्यपाल से उलझना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस समय यह मामला ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां लगता है कि तनाव के या दूसरे शब्दों में कहें, तो अशोभनीय व्यवहार के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। प्रोटोकॉल और परंपराओं का टूटना तो खैर इस राज्य के लिए कोई नई बात रही ही नहीं है। इस बार इसका नया कायदा राज्य के विश्वविद्यालयों को लेकर तैयार किया जा रहा है। कई दूसरे राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी राज्यपाल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर भी होते हैं। इस ओहदे के कारण राज्यपाल के पास कई अधिकार होते हैं। वह विश्वविद्यालयों को सीधे निर्देश दे सकते हैं और विश्वविद्यालय के कई कार्य उन्हीं की अनुमति से आगे बढ़ते हैं।

पश्चिम बंगाल ने चांसलर के तौर पर राज्यपाल को मिले ज्यादातर अधिकार अब वापस ले लिए हैं। राज्यपाल अब विश्वविद्यालयों को कोई भी निर्देश सरकार के जरिए ही भेज सकते हैं। विश्वविद्यालयों को भी कहा गया है कि वे अपने चांसलर से सीधे कोई निर्देश न लें। आमतौर पर राज्यपाल के चांसलर पद को मानद माना जाता है, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अब औपचारिक भी बना दिया है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि उसने इसे लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है, राज्यपाल के विश्वविद्यालयों को निर्देश देने की महज एक परंपरा थी और लोगों ने बस इसी को नियम मान लिया। मामला चाहे नियम का हो या परंपरा का, लेकिन इस निर्देश के बाद राज्यपाल और प्रदेश सरकार के रिश्ते एक नए रसातल तक पहुंच गए हैं। यह मामला तब शुरू हुआ था, जब पिछले दिनों राज्यपाल जाधवपुर विश्वविद्यालय गए, और वहां वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार वगैरह ने उनसे सहयोग करने से मना कर दिया था।

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तनाव का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों को रोक रखा है, इसलिए उन्हें विधानसभा में पेश नहीं किया जा पा रहा। हालांकि राजभवन का कहना था कि ऐसा सांविधानिक प्रावधानों के तहत ही किया गया है। इस मसले को लेकर विधानसभा परिसर में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन भी किया था और बाद में विधानसभा के सत्र को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल विधानसभा भवन पहुंचे, तो उन्हें वहां गेट बंद मिले। राज्यपाल का पद भारत का सबसे विवादास्पद सांविधानिक पद रहा है। कुछ लोग तो इस पद को खत्म करने के तर्क तक देते रहे हैं। पर इस पद का अपना ही महत्व और अपनी ही भूमिका रही है। कई प्रदेश सरकारों और राज्यपालों ने विचारधारा व दलगत भेद होने के बावजूद तनावों के बीच भी अपनी गरिमा का पूरा निर्वाह किया है। आज की राजनीति में गरिमा दुर्लभ हो गई है। याद रखना होगा कि ऐसे तनावों की कीमत आखिर में राज्य की जनता को ही चुकानी पड़ती है।

क्यों आंदोलित हो रहा है पूर्वोत्तर

उस रात जब संसद में नागरिकता कानून में बदलाव के लिए चर्चा चल रही थी, तब गुवाहाटी की सड़कों पर यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध में मार्च कर रहे थे। कुछ महीने पहले भी ऐसे विरोध-प्रदर्शन से असम में जनजीवन बाधित हो गया था। नारे वही थे, जोय आइ असम। चिंता वही थी, 'खिलोंजिया' (मूल निवासी) के अधिकार। जब आधी रात को लोकसभा ने संशोधन विधेयक पारित किया, तब असम के पड़ोसी राज्यों में भी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। भाजपा ने नागरिकता को फिर परिभाषित करने की नई कोशिश करके इस पुराने सवाल को जिंदा कर दिया है कि कौन स्थानीय है और कौन बाहरी? इस संशोधन का असम में सबसे मुखर और स्पष्ट विरोध चौंकाता नहीं है। असम के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें किनारे कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन राज्यों में यह कानून लागू नहीं होगा, जो इनर लाइन परमिट या छठी अनुसूची के दायरे में आते हैं। असम के कुछ ही जिलों में छठी अनुसूची लागू है। छठी अनुसूची जनजातीय परिषदों को ज्यादा स्वायत्तता देती है। चूंकि असम इनर लाइन परमिट वाला राज्य नहीं है, इसलिए यह पूर्वोत्तर का अकेला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां बांग्लादेश से आए अवैध हिंदू शरणार्थी बसाए जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर को आश्वस्त किया है कि उसे भी इनर लाइन परमिट व्यवस्था के दायरे में लाया जाएगा।

स्वाभाविक है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और अन्य अनेक नागरिक संगठन ठगा महसूस कर रहे हैं। जो असम समझौता हुआ था, उसमें सहमति बनी थी कि 1971 से पहले जो लोग असम में आ गए हैं, उन्हें नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन अब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 2014 तक आए अवैध शरणार्थियों को भी नागरिकता देगी। अकेले असम में लाखों लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। पूर्वोत्तर में 238 मूल जनजातियां ऐसी हैं, जो आस्था से हिंदू नहीं हैं। पूर्वोत्तर के सात राज्यों की जनजातियां परस्पर मिलकर रहने पर कमोबेश सहमत हैं, लेकिन बाहरी लोगों को यहां बसाने की किसी भी कोशिश के प्रति सभी सशंकित हैं। चिंता सभी बाहरी लोगों को लेकर है, धर्म यहां कतई मायने नहीं रखता। मिसाल के लिए, अरुणाचल प्रदेश बौद्ध चकमा को नागरिकता देना नहीं चाहता, मिजोरम ब्रू और रियांग को बसाना नहीं चाहता। ये तीनों जनजातियां बांग्लादेश से आई हैं। अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिशों के कारण जहां पहले से ही अस्थिर माहौल हो, वहां नागरिकता संशोधन विधेयक नए प्रकार के दोष ही पैदा करेगा। पूर्वोत्तर में पिछले दो दशकों में कमोबेश जो शांति रही है, उसका क्या होगा? क्या नए राष्ट्रीय कानून से इन राज्यों के छोटे जनजाति समूहों की नींद उड़ जाएगी? क्या यह एक स्थाई चुनाव मुद्दा बन जाएगा? भाजपा ने 2019 के राष्ट्रीय चुनावों में अपने घोषणापत्र में इस वादे को शामिल किया था। चूंकि लोकसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ी है, इसलिए पार्टी ने यह सोचा कि लोग इस विधेयक का समर्थन करेंगे। यह मानना वाजिब होगा कि असम के जिन मतदाताओं ने भाजपा सांसदों को चुना है, उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में मत दिया है। उन्हें शायद अब अपना कदम गलत लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाजपा ने असम को बाकी राज्यों से अलग कर दिया, ताकि इस कानून के विरोध की कमर टूट जाए। साथ ही, सत्ताधारी पार्टी के लिए पूरे पूर्वोत्तर से जूझने की बजाय केवल असम से निपटना आसान हो जाए। लेकिन भाजपा ने इस कानून के असर का गलत आकलन कर लिया है। जनजातियों में ज्यादातर लोग ईसाई हैं, वे इस कानून को शक की निगाह से देख रहे हैं। उन्हें लगता है, कानून का मकसद बांग्लादेश से आए हिंदुओं को बसाना है। उधर पिछले साल, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नागरिकता संशोधन विधेयक को भाजपा की चुनावी रणनीति बताकर खारिज कर दिया था। आगे चुनाव में क्या होगा, यह कहना मुश्किल है, पर इसमें शक नहीं कि इससे पूर्वोत्तर में तनाव बढ़ेगा। त्रिपुरा का उदाहरण सामने है कि कैसे कुछ ही दशकों में यहां के मूल निवासी 32 प्रतिशत आबादी तक सिमट गए। राज्य को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं। त्रिपुरा में बांग्ला बोलने वाली आबादी बहुसंख्यक हो गई है। ऐसी स्थिति कमोबेश क्षेत्र के दूसरे राज्यों में भी है। मेघालय के शिलांग में ही दस गुणा दस वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा इलाका है, जिसे यूरोपीय वार्ड कहा जाता है। यह छठी अनुसूची से बाहर है। इस इलाके में भारी आबादी है। कुछ इलाकों में झुग्गियां हैं, जहां बांग्लादेशी मूल के लोग ने कब्जे कर रखे हैं। कानून का विरोध करने वाले जानते हैं कि मेघालय में 1.70 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू हैं, जिनका दावा है कि उन्हें उनके देश में सताया गया। ऐसे लोग अब मेघालय और असम की बराक घाटी में बसना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां बांग्ला बोलने वाली आबादी पहले से ही बड़ी संख्या में रह रही है। मेघालय ने समाधान के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस कदम के राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? इस कानून के जरिए असम में चुनाव जीतने की योजना है या निशाने पर पश्चिम बंगाल है? पश्चिम बंगाल में कुछ लाख हिंदुओं को नागरिकता देकर भाजपा स्थाई वोट बैंक बना लेगी। यह ममता बनर्जी की उस तृणमूल कांग्रेस से लड़ने का एक तरीका है, जो मुसलमानों का अत्यधिक संरक्षण कर रही है, क्योंकि वे राज्य में एक मजबूत वोट बैंक हैं। पश्चिम बंगाल 42 सांसद और असम 14 सांसद भेजता है। दिलचस्प यह कि दोनों ही राज्यों में 2021 में चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर में बढ़ते तनाव को देखकर लगता है कि केंद्र सरकार को सीमा से आगे जाकर इस इलाके में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत में अनगिनत विविधताएं हैं। इस देश में शासन करने वालों में दूरदर्शिता व बड़ा दिल होना चाहिए, ताकि वे तमाम विभेदों का समावेश भी करें और पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं का भी पूरा ध्यान रखें।

भाजपा के राजनीतिक विमर्श की परीक्षा

झारखंड विधानसभा चुनाव न केवल इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस समय देश में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उनकी वजह से यह चुनाव पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव दो महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं के कुछ ही समय बाद हो रहा है। ये दो सामाजिक-राजनीतिक घटनाएं हैं- राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने की कोशिश में नाकाम होना। और साथ ही शरद पवार की राजनीतिक छाया तले महाराष्ट्र में विपक्ष का सफल और ताकतवर होकर उभरना भी अहम है। इन दोनों बड़ी घटनाओं से जनमानस पर जो असर हुआ है, झारखंड का चुनाव उसकी परख करेगा। यह पता चलेगा कि लोगों के मन में भाजपा के प्रति क्या भाव हैं? ये दोनों घटनाएं चुनाव में कहीं न कहीं अंतर्विरोधी प्रभाव भी पैदा कर सकती हैं। एक घटना भाजपा को मजबूत कर सकती है, तो दूसरी भाजपा के लिए नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है।

झारखंड मूलत: आदिवासी, प्रवासी और सदान (गैर आदिवासी स्थानीय निवासियों) की आबादी वाला राज्य है। सदान में मूलत: पिछड़ी जातियों की आबादी चुनावी रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिहार, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य भागों से कोयले और अन्य उद्योगों में काम करने के साथ व्यवसाय व व्यापार करने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी यहां आए और बसे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक लोकगीत गाया जाता है, फेंक देले थरिया, बलम गइले झरिया, पहुंचले कि ना। यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में आर्थिक तनावों से मुक्ति के लिए लोग प्रवासी बनकर झारखंड जाते रहे हैं। झारखंड की खदान या खनिज आधारित अर्थव्यवस्था लंबे समय से रोजगार देती रही है। बाहर से झारखंड आने का यह क्रम अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा है। इस चुनाव में भाजपा अपने राष्ट्रीय मुद्दों जैसे राम जन्मभूमि, अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति, तीन तलाक वगैरह के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और डबल इंजन सरकार जैसे मुद्दों को मिलाकर अपना चुनावी-विमर्श विकसित कर रही है। टिकट वितरण में सामाजिक गणित का ध्यान सभी दलों की तरह भाजपा की भी रणनीति का हिस्सा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का संयुक्त विपक्ष अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण जैसे स्थानीय मुद्दों के आधार पर भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है। जल-जंगल और जमीन की सुरक्षा का मुद्दा तो यहां हमेशा कारगर रहा है। पर्यावरण भी मतदाताओं के एक वर्ग और कुछ राजनीतिक दलों की चिंताओं में शामिल है। मुद्दों के टकराव के बावजूद इस बार के झारखंड चुनाव में आदिवासी, जनजातीय मतों का झुकाव चुनावी नतीजे तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आदिवासियों में कई तरह का असुरक्षा बोध दिखाई पड़ता है। उन्हें बाहर से आए सामाजिक समूहों से उभरे नेतृत्व पर विश्वास करने में समय लगता है। दूसरा, इनके बीच सत्ता प्रतिरोध से उभरे पत्थलगड़ी आंदोलन भी इस चुनाव में आदिवासी मतों की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकता है। साथ ही, छोटा नागपुर और संथाल परगना टेनेन्सी ऐक्ट में परिवर्तन की भाजपा सरकार की नाकाम कोशिश ने भी उनके बीच एक असुरक्षा बोध पैदा किया है। अब देखना यह है कि जनजातीय समूहों के एक भाग के बीच उभरे इन असुरक्षा बोध के तत्वों का क्या राजनीतिक अर्थ निकलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनके संबद्ध संगठन भी जमीन पर काफी प्रभावी ढंग से सक्रिय हैं। आदिवासियों के बीच असुरक्षा बोध के प्रभावों को कम करने की दिशा में इनके प्रयास जारी हैं। यह भी ठीक है कि यहां आदिवासी मत एक ही तरफ नहीं झुकते हैं। सामुदायिक और धार्मिक आधार पर आदिवासियों के राजनीतिक निर्णय कई बार अलग-अलग भी होते हैं। देखना है कि आदिवासी मत इस बार किस रूप में इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं? सदान मतों का सबसे प्रभावी महतो समुदाय भी भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजसू में विभाजित हो सकता है। प्रवासियों का मत विभिन्न स्थानीय और अपने-अपने सामाजिक संबंधों से तय हो सकते हैं। झारखंड चुनाव में भाजपा अपने संगठन के अंतर्विरोध से उभरती हुई स्थितियों को अपने पक्ष में करने में लगी है। उसके सामने विपक्ष विभाजित है। बहुकोणीय संघर्ष अनेक क्षेत्रों में दिख रहा है। इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। पर उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है, अपने सामाजिक आधारों को बचाए रखना और चुनावी रूप से उन्हें मजबूत करना। झारखंड के चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह अगर भाजपा को आशानुकूल परिणाम नहीं देते हैं, तो इससे भाजपा के भविष्य की चिंताएं काफी बढ़ जाएंगी। इसके विपरीत भाजपा इस चुनाव में अगर प्रभावी विजय पा लेती है, तो यहां चुनाव उसके गले की विजयमाला में एक और सुगंधित फूल बनकर गुंथ जाएगा। गौर करने की बात है कि पहले 16 राज्यों में भाजपा की सरकार थी। अब उसके राज्य धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। झारखंड अगर बचा, तो उसके हाथ से राज्यों के निकलते जाने की प्रक्रिया थमेगी। महाराष्ट्र चुनाव एक तरफ शहरी मध्य वर्ग, नौकरीपेशा वर्ग की निहित चाहतों का चुनाव था, तो दूसरी तरफ झारखंड चुनाव आदिवासी उपेक्षित जनों की आकांक्षाओं का भी चुनाव होगा। पिछड़े समूहों के कृषक भी इस चुनाव से अपने बेहतर भविष्य की राह देख रहे हैं। बच्चों का कुपोषण यहां की एक बड़ी समस्या है, शिक्षा की स्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। यह ठीक है कि ये मुद्दे भी जनता के एक वर्ग के दिमाग में राजनीतिक विकल्प तय करने में कहीं न कहीं होते हैं, पर अनेक किस्म के सामाजिक संबंध, अस्मिता बोध दलों की सांगठनिक मजबूती, विपक्ष की स्थिति, मतों का विभाजन, ये सब मिलकर झारखंड चुनाव में जीत-हार की दिशा तय करेंगे। इस चुनाव में कोई भी हारे या जीते, लेकिन जनतंत्र में गरीबों, उपेक्षितों और आदिवासियों की चाहत व आकांक्षा बनी रहेगी। देखना यह है कि हमारे राजनीतिक दल इन आकांक्षाओं को कितनी ईमानदारी से महत्व देते हैं। एक साथ बने छोटे राज्यों में झारखंड को विकास के क्रम में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की तुलना में अपनी बेहतरी भी सिद्ध करनी है।

आशंकाएं और टकराव

यह खतरा पहले से ही था। यह भी लगभग तय था कि भारत जैसे विशाल देश में नागरिकता संशोधन विधेयक अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग विमर्श को जन्म दे सकता है। खासकर, पूर्वोत्तर भारत की सामाजिक जटिलताएं जिस तरह की हैं, वहां इससे कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, यह बात पहले से ही कही जा रही थी। देश की नागरिकता और उसकी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने वाले इस विधेयक के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि वह एक तरह से असम के सिटीजन रजिस्टर का ही राष्ट्रीय विस्तार है। एक विचार यह भी था कि असम का सिटीजन रजिस्टर प्रकाशित होने के बाद से जो समस्याएं सामने आई हैं, यह विधेयक उनका भी कुछ हद तक समाधान देगा। इन सारी जटिलताओं के बारे में केंद्र और इन राज्यों की सरकारों ने भी सोचा ही होगा। इस विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विमर्श शुरू हुआ हो, ऐसी खबरें हमें नहीं मिली हैं। लेकिन वहां आंदोलन खड़ा होने, बंद के आयोजन और हिंसा की खबरें जरूर आने लगी हैं। यह बताता है कि अशंकाओं के बावजूद इस तरह की चीजों को रोकने के लिए जो प्रशासनिक तैयारियां होनी चाहिए थीं, वे नहीं हुईं, जबकि विरोध करने वाले अपनी पूरी तैयारी में थे और इसके पहले कि विधेयक राज्यसभा के पटल पर रखा गया, सड़कों पर विरोध और प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। पूर्वोत्तर भारत में मामला जटिल इसलिए भी है कि एक तो वहां के समाजों में अपनी अलग जातीय पहचान को लेकर संवेदनशीलता कुछ ज्यादा ही है। दूसरे, यह देश का वह इलाका है, जहां पड़ोसी बांग्लादेश से घुसपैठ कुछ ज्यादा ही हुई है। इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले इलाके इसके असर से भले ही कुछ हद तक बचे हों, लेकिन बाकी जगहों पर जनसंख्या का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में काफी तेजी से बदला है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ जगहों पर जनजातियों के लोग भाषाई अल्पसंख्यकों में बदल रहे हैं। इन स्थितियों में रहने वाले नागरिकता को लेकर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हैं, इसलिए नागरिकता संशोधन विधेयक वहां जनमानस को काफी खदबदा रहा है। वैसे यह उग्र आंदोलन इस विधेयक के लोकसभा में पास होने के बाद शुरू हुआ है, इसलिए यह पूरे देश की तात्कालिक परेशानी का कारण बन गया है, लेकिन यह भी सच है कि पूर्वोत्तर भारत में ऐसे आंदोलनों का एक इतिहास रहा है। खासकर, विदेशी नागरिकों को निकाले जाने को लेकर लंबा आंदोलन चलाने वाले असम को इस विधेयक ने कुछ ज्यादा ही परेशान किया है। एक कारण वह असम समझौता भी है, जिसके आधार पर नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया है। वहां लोगों को लगता है कि इस समझौते ने उन्हें जो दिया था, नया विधेयक उसे कुछ हद तक छीन रहा है। पूर्वोत्तर पर इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद क्या असर होगा, यह हमें अभी ठीक से नहीं पता, पर यह स्पष्ट है कि आशंकाएं समस्या को ज्यादा बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि वहां के लोगों के अधिकार इस विधेयक के चलते किसी भी तरह से नहीं छिनेंगे, लेकिन अगर इस तरह का आश्वासन पहले दिया जाता और स्थानीय स्तर पर विभिन्न जातीय समूहों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ा जाता, तो शायद इस टकराव से बचा जा सकता था।

लेटस्ट तस्वीरों में ग्लैमरस दिख रहीं काजल राघवानी

भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत ऐक्ट्रेसेस में से एक काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बार फिर से इतनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं कि फैन्स उन्हें देख फिदा हो रहे हैं। इन फोटोज में काजल ट्रडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उनका यह लुक भी सेक्सी वाइब्स दे रहा है। पहली पिक में काजल खूबसूरत पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहनी दिख रही हैं। उनके एक हाथ में स्क्रिप्ट देखी जा सकती है वहीं दूसरे से वह अपनी सेल्फी ले रही हैं। इस खूबसूरत तस्वीर के साथ काजल ने अपने फैन्स को 'गुड मॉर्निंग' विश किया, जिसने यकीनन फैन्स का दिन भी शानदार बना दिया। काजल का दूसरा फोटो भी उनके शूटिंग शेड्यूल के दौरान लिया गया दिखता है। वह मेकअप रूम में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने मिरर सेल्फीज लीं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया। इन फोटोज में वह एक हाथ से अपने बालों को पकड़कर मिरर में देखती नजर आ रही हैं। फोटोज के साथ क्या कैप्शन दिया जाए यह शायद काजल को भी समझ नहीं आया तभी तो उन्होंने फैन्स से भी पूछ डाला 'क्या लिखूं??

हाल ही में काजल को इंटरनैशनल भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स में भोजपुरी फिल्म 'संघर्ष' के लिए बेस्ट ऐक्ट्रेस लीडिंग रोल फिमेल का अवॉर्ड मिला है। अवॉर्ड मिलने की खुशी ऐक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फैन्स के साथ भी शेयर की थी। काजल राघवानी के फिल्मों की बात करें तो, वह फिल्म 'बाघी एक योद्धा' में सिंगर और ऐक्टर खेसारी लाल यादव के साथ नजर आई थीं। इसके अलावा हाल ही में वह रितेश पांडे के साथ उनकी फिल्म 'काशी विश्वनाथ' में भी नजर आई थी,जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था।

नींद की चिंता

चिंता को चिता के समान माना जाता है। यह दिन का चैन तो छीनती ही है, पर इसका सबसे दुखद और भयावह रूप वह होता है, जब यह रात की नींद भी छीन लेती है। कुछ लोग इसके चलते सो ही नहीं पाते और कुछ की नींद आधी रात अचानक टूटती है, तो सहजता से आती ही नहीं। करवटें बदल-बदलकर वे सोने की कोशिश करते रहते हैं, पर हर कोशिश बेकार जाती है। एक सोच यह भी कि आप कोशिश करते हैं, इसलिए सो नहीं पाते। नींद तो तभी आती है, जब आप किसी भी तरह की कोशिश बंद कर दें। यह भी कहा जाता है कि नींद से पहले सोचना बंद करो। लेकिन यह सब इतना आसान होता, तो हर कोई अपनी नींद पूरी कर ही लेता। नींद के लिए तरह-तरह के टोटके भी बताए जाते हैं। कोई गिनती गिनता है, कोई भेड़ों को गिनता है, तो कोई किसी का नाम जपता है। और मिर्जा गालिब तो यहां तक पूछ लेते हैं, कि जब हर किसी की मौत का एक दिन तय है, तो फिर नींद क्यों रात भर नहीं आती? वैज्ञानिक नींद न आने का एक बड़ा कारण चिंता को मानते रहे हैं, लेकिन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने इस बात को तो पहले की ही तरह स्वीकारा है, लेकिन इसमें कुछ नया भी जोड़ दिया है।

गृहमंत्री बाला बच्चन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की चर्चा

मुरैना। मप्र शासन के गृहमंत्री बाला बच्चन ने मुरैना प्रवास के दौरान गुरूवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चर्चा की तथा उनकी समस्याओं को सुना। गृहमंत्री ने पुलिस पुलिस लाइन स्थित प्रेस काफ्रेंस हॉल में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इसके उपरांत गृहमंत्री ने जेल प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मप्र शासन के गृहमंत्री बाला बच्चन ने मुरैना प्रवास के दौरान गुरूवार की शाम रेस्ट हाउस पर कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं चर्चा कर उसकी समस्याओं को सुना तथा उनकी समस्याओं से मुख्यमंत्री का अवगत कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश मावई सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के उपरांत गृहमंत्री बाला बच्चन ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिये पुलिस लाइन प्रेस काफ्रेंस हाल में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुये पुलिस अधिकारियों को जिले में कानून व्यवस्था दुरस्त करने के आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में मुख्य रूप आईजी, डीआजी, पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के अनकों अधिकारी मौजूद रहे। इसके उपरांत गृहमंत्री बाला बच्चन ने जेल प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिल प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कार्यक्रम के अंत में गृहमंत्री बाला बच्चन मुरैना विधायक रघुराज सिंह के निवास एमएस रोड स्थित कंषाना भवन पर पहुंचे। जहां विधायक श्री कंषाना के ताऊ स्व. श्रीकृष्ण सिंह कंषाना के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुये परिवारीजनों के प्रति शोक संवेदनाऐं व्यक्त की। तत्पश्चात गृहमंत्री बाला बच्चन रावत पुरा सरकार की ओर रबाना हो गये।

अवैध पत्थर से भरे ट्रैक्टर को जप्त करने पहुंची

फॉरेस्ट की टीम पर स्कॉर्पियो से रोककर किया हमला

भौंती -खोड़ । शिवपुरी जिले के करेरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नए अमोला सब रेंज प्रभारी मोहन स्वरूप गुप्ता पर अवैध खनन माफियाओं ने स्कॉर्पियो से रोककर हमला किया है। जिसमें उनको गंभीर रूप से घायल अवस्था में शिवपुरी रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमोला सब रेंज प्रभारी मोहन स्वरूप गुप्ता को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। की कुछ लोग करमई के जंगल से अवैध पत्थर की खदान से निकले पत्थर का ट्रैक्टर से परिवहन कर रहे हैं7 जिस पर मोहन स्वरूप गुप्ता एवं अपने अन्य दल बल के साथ कार्यवाही करने हेतु। पहुंचे परंतु जब तक खनन माफिया अपने ट्रैक्टर को तेज गति से भगाते हुए। नावली गांव के अंदर ले गये। ट्रैक्टर का पीछा वन विभाग की टीम द्वारा किया

जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर मालिक एवं अन्य खनन माफियाओं को इसकी सुचना दी जिस पर खनन माफियाओं द्वारा एक स्कॉर्पियो से वन विभाग की गाड़ी का रास्ता रोककर वन विभाग की गाड़ी चालक पर पहले तो 315 बोर का देसी कट्टा लगाया गया । और उसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया और वन विभाग के वाहन की भी जमकर तोड़फोड़ की जैसे तैसे वन विभाग के कर्मचारी अपने घायल डिप्टी रेंजर व अन्य कर्मचारियों की जान बचाकर भागे और घायल अवस्था में डिप्टी रेंजर अन्य कर्मचारियों को शिवपुरी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया इसके बाद खोड पुलिस चौकी पर घटना की जानकारी देते हुए 5 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा एवं प्राणघातक हमले जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की है।

जैन समाज की सामूहिक रथ यात्रा में सम्मिलित हुए हजारों श्रद्धालु

अम्बाह। जैनसमाज की दो दिवसीय वार्षिक रथयात्रा और श्रीजी का नगर भ्रमण महोत्सव जैन संत योगभूषण सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरूवार की दोपहर 2 बजे किला रोड से प्रारंभ हुआ इससे पूर्व विशाल रथ पर भगवान को विराजमान कर सम्पूर्ण बाजार से यह शोभायात्रा निकाली गई जो जैन बगीची पर जाकर समाप्त हुई। इस यात्रा में एक हजार से अधिक महिला पुरुष और बच्चे शामिल हुए,लगभग 70 वर्ष पुरानी इस रथयात्रा में आगरा के कलाकारों व्दारा बनाई आधा दर्जन अहिंसक और मर्यादित की झांकियां भी शामिल हुई, यात्रा का जगह जगह आरती उतारकर स्वागत किया गया वही मकान की छतों और बाल्कनियों से लोगों ने रथयात्रा का पुष्पवर्षा से स्वागत किया।

गुरुवार को अंबाह नगर में जैन समाज की वार्षिक रथयात्रा की धूम रही रथ यात्रा में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी श्रद्धालुओ ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान महावीर की आरती उतारी और शीश नवाया और पुष्प वर्षा की ज्ञात रहे की जैन समाज द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रथयात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसके तहत इस वर्ष गुरुवार और शुक्रवार को यह आयोजन किया जा रहा है छोटे जैन मंदिर से यह रथयात्रा जैन बगीची के लिए रवाना हुई इस रथयात्रा में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा ,रथ यात्रा की भव्य झांकी के दर्शन के लिए रास्ते भर लोग आरती के थाल हाथ मे लेकर खड़े रहे जुलूस में धार्मिक धुनों के साथ

बैंडबाजे वातावरण को आनंदमय बना रहे थे इसी दौरान युवा भगवान के जयकारों के संपूर्ण नगर को गुंजायमान कर रहे थे , कुछ स्थानों पर भवनों से ऊपर मौजूद भक्तों ने रथयात्रा पर पुष्प वर्षा की उक्त यात्रा जैसे-जैसे जैन बगीची की ओर बढ़ती गई भक्तों की भारी भीड़ यात्रा के साथ जुड़ती गई जैन बगीची पर पहुंचकर पांडुक शिला पर 108 कलशो से भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक किया गया रथ यात्रा में शामिल झाँकी लोगो को शिक्षाप्रद संदेश दे रही थी आयोजन को संबोधित करते हुए जैन संत योग भूषण जी महाराज ने कहा कि रथयात्रा कर्म का संदेश देती है कर्म और धर्म का संतुलन ही जीवन को सुचारु रुप से संचालित कर सकता है ऊंच-नीच अमीर गरीब जाति धर्म आदि हर प्रकार का भेदभाव भुलाकर सामूहिक रूप से स्वयं के हाथों से रथ पहियों को गति देने का कार्य मानव को उसकी शारारिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का परिचय कराता है इस अवसर पर जैन मंदिर कमेटी की अध्यक्ष जिनेश जैन ने रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि यह रथयात्रा हमारी सामाजिक एकता शक्ति और धार्मिकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि रथयात्रा को भव्य बनाने का प्रयास आगामी वर्षों में भी जारी रहेगा।

कवि सम्मेलन आज देश के प्रख्यात कवि करेंगे काव्य पाठ

जैन समाज अम्बाह द्वारा वार्षिक रथयात्रा महोत्सव के तहत आज 13 दिसंबर को जैन बगीची परिसर के सांस्कृतिक रंगमंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें देश के प्रख्यात कवि काव्य पाठ के जरिये लोगो का मनोरंजन करने के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर कविता पाठ करेंगे जैन समाज के अध्यक्ष जिनेश जैन के अनुसार इस कवि सम्मेलन में वीर रस के कवि मनवीर मधुर मथुरा, संजय खत्री बेटाम हास्य, पार्थ नवीन प्रतापगढ़ हास्य पैरोडी, मोहन मुंतज़रि गीतकार, नेहा दुबे रायपुर , कमलेश जैन सहित अन्य कवि पधारेंगे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जिनेश जैन में समस्त नगरवासियों से रात्रि 8बजे जैन बगीची परिसर में पहुंचकर कवि सम्मेलन का आनंद लेने की अपील की है वही आज समस्त समाज जनों के भोज का आयोजन नरेश काका व्दारा किया गया है।

शाकंबरी माता को 11हजार फीट की चुनरी अर्पित करेंगे

(डॉ शम्भू पंवार)

चिड़ावा राजस्थान सीकर। जिले में स्थित शक्तिपीठ माता शाकंबरी के प्रकट उत्सव पर 11,000 फुट की चुनरी माता रानी को अर्पित की जाएगी । यात्रा के सह संयोजक अजय चौमाल चिड़ावा, ने बताया की माता रानी को अर्पित की जाने वाली चुनरी पूरे देश भर में शाकम्बरी कुटुंब द्वारा तैयार की जा रही है। फिर इन सभी चुनरियो को उदयपुरवाटी कस्बे में एक साथ जोड़ कर 11000 फुट लंबी चुनरी भक्तगण शाकंबरी माता तक पदयात्रा के रुप मे लेकर जाएंगे, वहां प्राकट्य दिवस 10 जनवरी को माता रानी को अर्पित करेंगे। इसी क्रम में चिड़ावा में में भी प्रोफेसर कन्हैया लाल लाठ के निवास पर शाकंबरी कुटुंब की महिलाएं ममता चौमाल, प्रियंका शर्मा, अनीता लाठ,ऋचा सुल्तानिया, इंदिरा डारा, सुमन सुल्तानिया, किरण गुप्ता, रेनू चौमाल, बड़ी श्रद्धा और उत्साह से माता रानी के भजन कीर्तन करते हुए चुनरी पर बूटियां लगाकर तैयार कर रही हैं। ऐसी प्रक्रिया पूरे देश भर में माता रानी के भक्त कर रहे हैं।

राज्यपाल ने डॉ आकांक्षा शर्मा को 2गोल्ड मैडल से सम्मानित किया

चिड़ावा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के दीक्षांत समारोह राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने चिड़ावा के शिक्षक एवं कवि अनिल शर्मा अनमोल की सुपुत्री डॉ आकांक्षा शर्मा को आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वर्ष 2017 में टॉप करने पर दो स्वर्ण मैडल प्रदान कर सम्मानित किया। डॉ शर्मा को एक गोल्ड मैडल आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा तथा एक गोल्ड मैडल डाबर कंपनी द्वारा प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी थे एवं विशिष्ट अतिथि राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा थे। डॉक्टर आकांक्षा शर्मा की इस उपलब्धि पर नगर की सामाजिक,साहित्यिक संस्थाओं ने चिड़ावा का नाम रोशन करने पर खुशी जाहिर करते हुवे बधाई दी है।

बेटा पढ़ाओ - संस्कार सिखाओ अभियान

मुझे तो ये सारा समाज ही गुनहगार नज़र आता है : कवयित्री हिमांशी गौड़

लक्ष्मणगढ़/सीकर(अर्पित गुप्ता) लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी के प्रसिद्ध कवि हरीश शर्मा द्वारा आयोजित बेटा पढ़ाओ - संस्कार सिखाओ अभियान पर जयपुर निवासी युवा कवयित्री हिमांशी गौड़ ने अभियान पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारों के माध्यम से कहा कि ए सखी मैं निशब्द हूँ, जो हुआ जानकर स्तब्ध हूँ। कैसे तेरे अपनों को दिलासा दे जाऊँ मैं, ये समाज बदलेगा ये कैसे कह जाऊँ मैं,क्या करूँ ऐ सखी मुझे समझ नहीं आता है, मुझे तो ये सारा समाज ही गुनहगार नज़र आता है। ये रूह से कितना खोखला कितना निरर्थक है क्या है जो नारी सम्मान को सार्थक है। क्या करूँ ऐ सखी ये कैसी लाचारी है, इस समाज में कीड़ों से भी ज्यादा व्यभिचारी है, सौम्यता को छोड़ कर मै दुर्गा बन जाऊँगी। हर माँ को महाकाली बनना सिखलाऊंगी। या तो माँ अपनी बेटियों को क्षत्रिय बनाएगी। या फिर हर बेटा संस्कारित हो जाएगा, रोली,

यदि अब भी एक संस्कारित समाज का निर्माण ना किया गया तो प्रलय व सर्वनाश को कोई नहीं रोक पाएगा

अक्षत चंदन जैसा मां तूने तो बनाया था, लेकिन मै शस्त्र उठाकर स्वयं अस्त्र बन जाऊंगी। फिर हर बलात्कारी बेटे का दाह संस्कार हो जाएगा। दानावल की इस बेला में या तो प्रलय रुक जाऐगी या इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। और जो ये न हुआ तो महाकाली तांडव मचाएगी और इस तांडव को स्वयं महाकाल भी रोक न पाएगा। यदि अब भी एक संस्कारित समाज का निर्माण ना किया गया तो प्रलय व सर्वनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर प्रलय व सर्वनाश को रोकना है तो सबसे पहले अपने बेटों को शिक्षित के साथ-साथ संस्कारित करें व अभियान के आयोजनकर्ता कवि लेखक हरीश शर्मा के क़दमों से कदम मिलाकर साथ चले। अब हम सब को इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए समाज व देश की समस्त बहिन-बेटियों की सुरक्षा करनी होगी।

किसान की बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी समाज का किया नाम रोशन

भोपाल-बेटियां हैं उन्हें फूल की तरह खिलने दें पढ़ने दें खेलने दें और समाज उन्हें सुरक्षा प्रदान करें इसके बाद देखें कि ये बेटियां कैसे देश की शोभा में चार चांद लगाती है हमारे सभ्य समाज में लड़कियों को देखने का नजरिया बदलना होगा।भोपाल में 8 दिसंबर से चल रहे ताइक्वांडो चैपियनशिप में मंगलवार को भोपाल निवासी श्री मुकेश रजक की पुत्री खुशबू रजक ने ताईक्वांडो चैपियनशिप मे गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया आपको बता दें खुशबू रजक के परिवार के लोग खेती किसानी करते हैं और उनके पिता एक किसान है आपको बता दें कि जब खुशबू अपनी समाज के सामने नाम रोशन कर घर लौटी और बेटी के पास गोल्ड मेडल देखकर माता पिता की आंखें में आंसू से भीग गई किसान मुकेश रजक ने कभी भी अपनी बेटी को आगे बढ़ने से नहीं रोका मंगलवार को जब खुशबू रजक अपने घर पहुंची तो उसे गले लगाकर माता पिता खुद के आंसू नहीं रोक सकें मुकेश रजक ने कहा कि बेटी ने मेरा नाम दुनिया और समाज के सामने रोशन किया है मुझे अपनी बेटी खुशबू पर गर्व है।

जब इस संबंध में खुशबू रजक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस गेम में आगे बढ़ना आसान नहीं था क्योंकि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने न तो इस गेम को कभी खेला है और न ही इस गेम के बारे में कोई जानकारी थी बावजूद इसके न मेरे परिजनों और न ही मैने कभी हौसला हारा ओर तमाम मुश्किलों के बावजूद में आगे बढ़ती रही।

रजक महासंघ मध्यप्रदेश के संरक्षण गोर्वधन धारवा और प्रदेश अध्यक्ष केशलाल रजक प्रदेश महासचिव बल्ली रजक(राम भरत) कार्यकारी अध्यक्ष ओपी बाथरी ने कहा कि बेटी को पढ़ा लिखा कर शादी करने के बाद चूल्हा चौका तक सीमित रखना अब पुरानी बात हो गई है बेटियां हर क्षेत्र में अपना व परिजनों का नाम रोशन कर रही है गरीबी में पली बढ़ी हेमादास हो या फिर कुश्ती के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली फोगट बहनें उनकी राह पर अब हमारे प्रदेश की ओर समाज की बेटी खुशबू रजक भी चल पड़ी है किसान माता पिता की बेटी खुशबू रजक के अपने जूनून को सीढ़ी बनाकर कामयाबी के शिखर पर पहुंची है। वहीं रजक समाज में आयुक्त निःशक्तजन कमिश्नर संदीप रजक ने कहा कि यह सम्मान हमारी रजक समाज के लिए गर्व की बात है एक सामान्य एवं किसान परिवार की बेटी ने अपने जज्बे और आत्मविश्वास के बल पर अपने माता पिता और परिवार नाम रोशन किया अपनी समाज की बेटी ने संसाधनों के अभाव में अपने हौसले के दम पर इस खेल के क्षेत्र में प्रदेश और अपनी रजक समाज का नाम रोशन किया है। खुशबू रजक की इस जीत पर रजक महासंघ मध्यप्रेदश संरक्षण गोर्वधन धारवा प्रदेश अध्यक्ष केशलाल रजक प्रदेश महासचिव बल्ली रजक(रामभरत) कार्यकारी अध्यक्ष ओपी बाथरी मध्यप्रदेश आयुक्त निःशक्तजन कमिश्नर संदीप रजक झाबुआ से चेतना चौहान रवि रजक अशोक रजक विजय रजक सुरेश कनौजिया अल्केश रजक मोनू रजक शीतल रजक उमेश रजक धर्मेंद्र रजक हिलौंदा सागर से प्रवीन रजक पुष्पेंद्र रजक दमोह रामलाल प्रणमी तेन्दूखेड़ा से रजक समाज अध्यक्ष भागीरथ रजक पाटन से रोहित रजक विजय रजक भुवनेश्वर रजक धनश्याम रजक लक्ष्मीकांत रजक कृष्णपाल रजक दादू हिलौधा सधीरन प्रसाद रजक कोदूलाल रजक भूपेंद्र रजक सतीशराज रजक रोहिणी रजक अंकिता रजक चाहना रजक आशीष रजक सिंगरौली राजेश रजक एवं सभी रजक समाज के लोगों ने खुशबू रजक और उनके परिवार के लोगों को बधाई दी है और खुशबू रजक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते है।

मधुशाला के कार्तिक मन्तशा सम्मानित

उदयपुर, अर्पित गुप्ता । काव्यांगन सहित्यिक संस्थान उदयपुर द्वारा विज्ञान भवन उदयपुर में एक विशाल काव्य महोत्सव काव्य कॉकटेल का आयोजन बड़े हर्षोउल्लास से किया गया,इस कार्यक्रम में शहर के 30 से अधिक कवियों ने भाग लिया। इस दौरान मधुशाला सहित्यिक परिवार के सबसे छोटे साहित्यकार मंतशा खान एवं कार्तिक राज गुर्जर ने श्रेष्ठ काव्य पाठकिया और अपने सुंदर काव्य पाठ हैतु दौनो साहित्यकारों सम्मानित किया गया गया। इस उपलब्धि पर मधुशाला परिवार की अध्यक्ष मधु जैन और संस्थापक दीपेश पालीवाल में इस उपलब्धि के लिए दोनो साहित्यकारों बधाई दी।

भारतीय किसान संघ जाएगा गांव-गांव, करेगा ग्रामसंपर्क अभियान

रिपोर्टर धीरज ओझा

बैराड़। तहसील क्षेत्र में भारतीय किसान संघ बैराड़ द्वारा गुरूवार को बैठक आयोजित की गई। जिसमें श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्मशताब्दी बर्ष के उपलक्ष्य में ग्रामसंपर्क अभियान किया जा रहा है जिसके अंतर्गत बैराड़ तहसील के सभी ग्रामों व मंडल केन्द्रों पर किसानों को जैविक खाद, किसान संगठित हों व किसान संघ के बारे में जानकारी, साथ ही नशा मुक्त मानव, जहर मुक्त खेती के नारे के साथ किसानों के बीच जाकर ग्रामसंपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है जोकि 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक चलेगा। बैठक में कार्यकर्ताओं को बताते हुए तहसील अध्यक्ष बृजेश धाकड़ ने कहा कि राष्ट्र ऋषि महादेव श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने विदेश भ्रमण 650 किसान प्रतिनिधियों को एकत्रित कर 4 मार्च 1979 को राजस्थान के कोटा में भारतीय किसान संघ की स्थापना की जो किसानों के द्वारा किसानों के लिए काम करने वाले गैर राजनैतिक, राष्ट्रवादी अखिल भारतीय संगठन है। जिसका सपना है स्वाबलंबी किसान, संपन्न ग्राम, समर्थ भारत जिसकी कार्यपद्धती है हर किसान हमारा नेता है हम संगठन से आंदोलन आंदोलन से संगठन करते हुए रचनात्मक कार्य करते हैं जिससे

भारतवर्ष में है साथ ही बताया कि किसान संघ बर्षभर में 4 मुख्य कार्यक्रम करता है जिनमें प्रमुख स्थापना दिवस, बलराम जयंती किसान दिवस, गौमाता पूजन, भारतमाता पूजन है बैठक मे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी भी दी गई। बैठक मे मुख्य रूप से रमेश यादव भौराना पूर्व जनपद उपाध्यक्ष,केशव सिंह (फौजी) यादव जैविक प्रमुख,बृजेश धाकड़ तहसील अध्यक्ष, योगेश बर्मा तहसील मंत्री, किशन यादव मंडल अध्यक्ष खटका, तहसील कार्यकारिणी सदस्य कैलाश पटेवरी वाले, दीनदयाल शर्मा मंडल अध्यक्ष गोवर्धन, गणेश धाकड़ तहसील कार्यकारिणी सदस्य, प्रिन्स प्रजापति पत्रकार, बिष्णु धाकड़, जगदीश धाकड़ तहसील मंत्री।

6 जुआरियों को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। जिला मुरैना के एडीपीओ/मीडिया सेल प्रभारी चंचल मोदी ने घटना के बारे मे संक्षेप मे बताया कि 28 अक्टूबर 2019 को थाना कोतवाली पुलिस ने दुर्गापुरी कॉलौनी मस्जिद के पास मुरैना से जुआ खेलते हुए आरोपीगण वंटी प्रजापति पुत्र रामवरन प्रजापति, सुमेर सिंह पुत्र धनीराम, रामशंकर पुत्र रामस्वरूप, महबूब खां पुत्र नूर खां निवासीगण दुर्गापुरी कॉलौनी मुरैना, महेन्द्र बाथम पुत्र हीरालाल निवासी संजय कॉलौनी मुरैना एवं देशराज पुत्र नवाब सिंह निवासी गणेशपुरा मुरैना पकडें थे। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना के न्यायालय मे पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपीगण को दोष सिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100-100 रूपये कुल 600 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

सट्टा मामले में आरोपी दण्डित

मुरैना। जिला मुरैना के एडीपीओ/मीडिया सेल प्रभारी चंचल मोदी ने घटना के बारे मे संक्षेप मे बताया कि 3 दिसम्बर 2019 को थाना कोतवाली के सउनि आरके वर्मा ने आरोपी भगवानदास राठौर पुत्र रामरतन राठौर को महावीर पुरा मुरैना से सट्टा गतिविधि चलाते हुए गिरतार किया था। पुलिस ने सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुरैना के न्यायालय मे पेश किया।

जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु हमेशा खड़ी रहूँगीं : इमरती देवी

ग्वालियर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु वह एक मंत्री, विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में हमेशा खड़ी रहेंगी। जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिलौआ में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी गुरूवार को डबरा जनपद पंचायत के शासकीय जवाहर माध्यमिक विद्यालय परिसर बिलौआ में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह राठौर ने की।

कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर श्री टी एन सिंह, एसडीएम डबरा श्री आर के पाण्डेय, जनपद पंचायत डबरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुलदीप श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिध एवं जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। शुरू में विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने ÷आपकी सरकार आपके द्वार÷ कार्यक्रम में शासन की विभिन्न हितग्राही एवं रोजगारमूलक योजनाओं के तहत एक करोड़ 4 लाख से अधिक के हितलाभ दिए। शिविर में दिव्यांग श्री राकेश प्रजापति को रेडक्रॉस से 5 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदाय की गई। मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी सरकार आपके द्वार÷ कार्यक्रम के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित होकर जनता की समस्याओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आवेदन जिनका निराकरण शिविर में संभव नहीं हो सका है, उन आवेदकों को परेशान एवं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदनों के निराकरण हेतु समय-सीमा निर्धारित कर अवगत कराया जायेगा।

श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि डबरा अनुविभाग के तहत छीमक में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अयोजित किया जा चुका है। जबकि अगला शिविर पिछोर में आयोजित होगा। इन शिविरों में ग्रामीण अपनी समस्यायें खुलकर रखें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद एवं दुआओं के कारण आज इस मुकाम तक पहुँची हैं। उनकी जवाबदारी है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु वह मंत्री, विधायक नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में हमेशा खड़ी रहेंगीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को दूरभाष पर भी उन्हें अवगत करा सकते है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री मोहन सिंह राठौर ने आवेदकों से आग्रह किया कि वह अपने आवेदन पत्रों का पंजीयन अवश्य कराऐं। ऐसे आवेदक जिनका निराकरण शिविर में संभव नहीं होगा, उनके निराकरण के लिए समय-सीमा दी जायेगी। उन्होंने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की कि कार्यक्रमों में अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु पुष्पाहारों एवं गुलदस्तों पर व्यय की जाने वाली राशि बच्चों को पाठ्यपुस्तक देने के लिए उपयोग की जायेगी। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का अधिकारी पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण की कार्रवाई करेंगे। वे भी समय-सीमा के पत्रों की बैठक में समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों के संबंध में अपर कलेक्टर श्री टी एन सिंह को प्रभारी बनाया गया है। बिलौआ क्षेत्र में दिन के समय निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बिलौआ में आधार पंजीयन केन्द्र एवं गेहूँ उपार्जन हेतु केन्द्र शुरू करने के भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री चौधरी ने सर्दी के मौसम को देखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिलौआ को निर्देश दिए कि नगर का रात्रि में भ्रमण कर सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में राज्य शासन की मंशा के अनुरूप विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई है।

महाराज मान सिंह तोमर को

तानसेन सामारोह में मप्र सरकार ने राजनीतीक कारण से किया दरकिनार

ग्वालियर। प्रेस नोट जारी करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कारकारयणी अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह तोमर, महाराजा मानसिंह संगीत महा विद्यालय के सचिव राजीव भदौरिया (गुड्डू) श्याम सिंह तोमर ने खेद ब्यक्त करते हुए कहा है कि - तानसेन समाहरोह जैसे गरिमामयी कार्यक्रम को मध्य प्रदेश सरकार राजनैतिक प्रतिबद्धता की बलि चढ़ा रही है। सरकार भली भांति जानती है कि ता सेन कि शिक्षा बादल गढ़ मे महाराजा मानसिंह संगीत विद्यालय मे हुई थी। महाराजा मान सिंह ने ही ध्रुपद का अविष्कार किया था। महाराजा मानसिंह द्वारा मानसिंह मंदिर ग्वालियर दुर्ग पर स्थित है वह भी ध्रपद कला का अद्वितीय उदाहरण है इन दोनों को दरकिनार करते हुए बिरला द्वारा बनबाये गये सूर्य मंदिर की थीम पर मंच बनाया गया है सूर्य मंदिर की स्थापना अभी कुछ साल पहले हुई है तानसेन यथार्थ है महाराजा मानसिंह कला संस्कृति का उल्लेख तक नहीं है ग्वालियर चम्बल अंचल के बारे मे सारे देश के संगीत व कला प्रेमियों के मन मे तो महाराजा मानसिंह के प्रति आदर है सरकार की नीतियों से कस्ट पंहुचा है।

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन में सर्वेयर एप से होगा क्वालिटी परीक्षण

ग्वालियर। खरीफ विपणन 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन में क्वालिटी परीक्षण सर्वेयर एप के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम उपार्जन समिति द्वारा नियुक्त सर्वेयर का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर खरीदी लॉगिन से किया जाएगा। पंजीयन करने के लिए सर्वेयर की एजेंसी का नाम चयन करने के बाद अन्य जानकारी प्रविष्ट की जाएगी। पंजीयन के पश्चात सर्वेयर के मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से पासवर्ड प्रेषित किया जाएगा जो कि पोर्टल पर पहली बार लॉगिन करने पर बदलना होगा। ई उपार्जन सर्वेयर एप को ई-उपार्जन की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए ई-उपार्जन की वेबसाईट को मोबाईल पर खोलना होगा तथा मोटा अनाज खरीदी 2019-20 पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सर्वेयर मोटा अनाज पर क्लिक करना होगा। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए जिला, केन्द्र और सर्वेयर चुनकर पासवर्ड अंकित करना होगा। लॉगिन होने के पश्चात पासवर्ड बदलना होगा तथा सर्वेयर एप की लिंक प्रदर्शित होगी। लिंक पर क्लिक कर ई-उपार्जन सर्वेयर एप को डाउनलोड करना होगा।

दिव्यांग सतेन्द्र ने बुलंद हौंसलों से फहराया परचम

ग्वालियर। कहते हैं कि हौंसलों से क्या कुछ नहीं हो सकता, हौंसले बुलंद हो तो शत प्रतिशत शारीरीक रूप से दिव्यांग भी उंचे से उंचा पहाड़ लांघ जाता है। कठिन से कठिन काम भी ऐसे लोगों के लिए बेहद आसान हो जाता है। जी हां ऐसा ही एक नाम ग्वालियर मध्यप्रदेश निवासी सतेन्द्र सिंह लोहिया का है। दरअसल सतेन्द्र ने अपने बुलंद इरादों से विश्व पटल पर परचम फहराया है। साथ ही शहर व प्रदेश का नाम भी दुनिया में रोशन किया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अमेरिका की 42 किमी लंबी कैटलीना चैनल को पार कर एशियाई रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसके साथ ही यह उपलब्धि हासिल करने वाले 32 वर्षीय सत्येंद्र ने अपनी दिव्यांगता की कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपने लिए एक शानदार जीवन की पहल की और एशिया के प्रथम दिव्यांग पैरा तैराक बन गए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद सत्येंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज हाथों में लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। सतेन्द्र मध्यप्रदेश शासन के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से भी 2014 में सम्मानित किये जा चुके है। मप्र के दिव्यांग पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने कैटलीना चैनल को 11 घण्टे 34 मिनिट मे पार किया और वे अपनी टीम के साथ इस चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक भी बन गए है, उन्होंने पिछले साल 2018 में इग्लैंड में स्थित इंग्लिश चैनल को भी 12 घण्टे 24 मिनिट में तैरकर एशियाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। साथ में उन्होंने अभी तक सात नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेकर 24 पदक प्रदेश के लिये हासिल किए है और तीन अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में, देश के लिए एक गोल्ड मैडल के साथ 4 पदक हासिल किये है। सेंट कैटलीना आइलैंड पार करने के अनुभव को लेकर सत्येंद्र ने बताया कि सुबह 10:57 बजे सेंट कैटलीना आइलैंड से शुरुआत की। लगातार तैराकी के बाद देर रात 10:30 बजे लॉस एंजिलस में सफर खत्म हुआ। सत्येंद्र की टीम में पांच अन्य खिलाड़ी थे। टीम ने कैटालीना चैनल को 11 घंटे 33 मिनट में पार किया है। सत्येंद्र ने बताया कि मैं 2018 में इंग्लिश चैनल पार कर चुका था। उसका अनुभव मुझे यहां काम आया। सत्येंद्र ने बताया कि कैटलीना को पार करना आसान नहीं है। यहां काफी तेज हवाएं चलती है जो आपकी गति को प्रभावित करती है। कैटलीना चैनल कई जगह काफी गहरी भी है। इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

वेसली नदी भिंड में सीखी तैराकी–सत्येंद्र ने गांव की वेसली नदी में तैराकी का ककहरा सीखा। दोनों पैरों से दिव्यांग सत्येंद्र ने अपनी कमजोरी को ही हुनर बना लिया और लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के प्रो. डॉ वी. के. डबास से तकनीकी रूप से तैराकी की तैयारी की।

आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को ओपीडी में मिलेंगी निःशुल्क सेवाएँ

ग्वालियर। प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राहियों को एचआईव्ही, कैंसर, आकस्मिक चिकित्सा और लावारिस मरीजों को ओपीडी सेवाएँ निःशुल्क मिलेंगी। आज जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री निशांत वरवड़े ने प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, सागर, विदिशा, दतिया, खण्डवा, रतलाम, शिवपुरी, शहडोल, छिंदवाड़ा स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों के अधिष्ठाता और अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

गौशाला में गायों को सर्दी से बचाव के लिए कलेक्टर ने दिया तीन लाख रूपए का चैक एवं 100 कम्बल

कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों ने किया गौशाला का निरीक्षण, अन्य क्षेत्रों में देखी साफ-सफाई व्यवस्था

ग्वालियर। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी एवं नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने आज गुरुवार को लाल टिपारा स्थित गौशाला का निरीक्षण किया तथा लाल टिपारा गौशाला एवं मार्क हॉस्पिटल परिसर की गौशाला में रहने वाली गायों के बेहतर रखरखाव एवं सर्दी से बचाव के आवश्यक प्रबंध करने के लिए तीन लाख रूपए का चैक गौशाला समिति को उपलब्ध कराया तथा गायों के लिए सौ कंबल देने के लिए भी कहा द्य इसके साथ ही दोनों गौशालाओं में रखे गए गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक वृहद पशु चिकित्सा कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए इसके लिए उन्होंने आसपास के सभी पशु चिकित्सकों को निर्देशित करने एवं कैंप आयोजित करने के

निर्देश दिए जिससे सभी गाय का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके द्य वहीं गौशाला के पास कैंट क्षेत्र के ट्रेंचिंग ग्राउंड को व्यवस्थित करने हेतु कलेक्टर श्री चौधरी ने नगर निगम द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए इसके साथ ही क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री चौधरी ने सात नंबर चौराहे के पास एक गैरेज मालिक द्वारा बाहर रोड पर कंडम वाहन रखे गए थे जिन्हें तत्काल जप्त कराने तथा संबंधित संचालक के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए द्य इसके साथ ही निगमायुक्त को यह भी निर्देश दिए की शहर भर में अभियान चलाकर सड़कों पर जहां भी कंडम वाहन खड़े हैं उन्हें तत्काल जप्त कराया जाए द्य साथ ही सात नंबर चौराहे के पास ही एक अन्य अतिक्रमण को तत्काल मौके पर ही मदा खलत बुलवाकर हटवाया गया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश, एसडीएम श्रीमती जयति सिंह, अपर आयुक्त श्री आरके श्रीवास्तव, सहित सभी संबंधित अधिकारीगण एवं साडा के पूर्व अध्यक्ष श्री राकेश जादौन भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवा प्रदान न करने के कारण

ग्वालियर। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पात्र व्यक्तियों को सेवा प्रदान समय-सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। समय-सीमा में सेवा प्रदान न करने पर संबंधित अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित किए जाने का भी प्रावधान है। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जिले के 10 अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवा प्रदान न करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तीन दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत पात्र व्यक्ति को समय-सीमा में सेवा प्रदान न करने पर एसडीएम झाँसी रोड़ श्री अनिल बनवारिया, नायब तहसीलदार तहसील डबरा श्रीमती पूजा मावई, सीईओ जनपद पंचायत भितरवार श्री अशोक कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार पुरानी छावनी श्री धीरेन्द्र गुप्ता, सीईओ जनपद पंचायत डबरा श्री कुलदीप श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार बिलौआ श्री श्यामू श्रीवास्तव, थाना प्रभारी थाना बिलौआ श्री अखिलेश पुरी गोस्वामी, नायब तहसीलदार पिछोर तहसील डबरा श्री आनंद किशोर गोस्वामी शामिल हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, एवं संपादक-भरत सिंह चौहान। पुष्पांजली प्रिंटर्स-गोवर्धन कॉलेनी, भिण्ड रोड, गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) से मुद्रित एवं दीपू इलेक्ट्रोनिक्स, पंजीयन क्रमांक/ एम.पी.एच.आई.एन. /31130 नियर हनुमान मंदिर, गोवर्धन कॉलोनी, भिण्ड रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक - भरत सिंह चौहान E-mail : pushpanjalitoday17@gmail.com 0751-4901333, M.: 8269307478